सान्ध्य हिन्दी दैनिक | जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 168 | जौनपुर, बुधवार, 05 फरवरी 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

हम महाकुंभ में हुई घटना की गहराई तक जाएगे : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महाकुंभ में भगदड़ पर की गई टिप्पणी के लिए अखिलेश यादव की आलोचना की और कहा कि सामलवादी पार्टी महाकुंभ पर झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि सनातन और प्रयागराज की घटना के खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेस और सपा ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा और कांग्रेस सतनात विरोधी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान शर्मनाक है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य हास्यास्पद है। अखिलेश पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा ये लोग 12 बजे सोकर उठते हैं, पार्टी कार्यालय जो उन्हें प्रेस नोट बनाकर देता है, वही पढ़ देते हैं। हमने बार–बार कहा है कि 40–45 करोड़ लोग स्नान यहां करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लोग पहले दिन से चाहते थे की महाकुंभ में कोई अनहोनी हो। उन्होंने कहा कि अखिलेश का चरित्र सनातन विरोधी है। महाकुंभ की घटना पर शरारती तत्व झूठ फैला रहे हैं। सीएम ने दावा किया कि शरारती तत्व चाह रहे थे कि घटना और ज्यादा बड़ी हो जाए। खड़गे और अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं में सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने की होड़ लगी हुई है की कौन कितनी ज्यादा सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करे। उन्होंने कहा कि संसद में इन्होंने जो बयान दिया है यह इनकी सनातन धर्म विरोधी चरित्र को दिखाता है और यह बताता है की यह सनातन धर्म से कितनी नफरत करते हैं। महाकुंभ पर इनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। भगदड़ को लेकर योगी ने कहा कि यह एक दुखद घटना थी। मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यह अपने आप में एक उदाहरण है। उस दिन करोड़ों लोग प्रयागराज में थे। ये दोनों दल और सनातनी विरोधी चाहते थे कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता दुर्घटना–मुक्त मेला सुनिश्चित करना था, दुर्भाग्य से यह घटना हुई...हमने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और मौद्रिक मुआवजे की घोषणा की। जानमाल के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती लेकिन हमने हरसंभव प्रयास किये। उन्होंने कहा कि घायलों को इलाज मुहैया कराया गया। हमने इसके लिए एक न्यायिक आयोग भी बनाया। लेकिन हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करना थी। पिछले 22 दिनों में 38 करोड़ श्रद्धालु यहां आए हैं। अगले 22–23 दिनों में और भी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हम 29 जनवरी को हुई घटना की गहराई तक जाएंगे।

गैरजिम्मेदार राजनीति में लिप्त हैं राहुल गांधी- राजनाथ सिंह

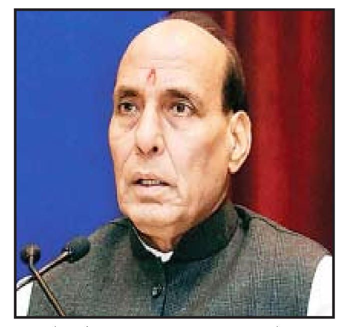

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 फरवरी 2025 को संसद में अपने भाषण में भारत–चीन सीमा पर स्थिति पर सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठे आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा था कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे इनकार रहे हैं। लेकिन सेना इस बात से सहमत नहीं है। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्री ने लिखा– सेना प्रमुख की टिप्पणी में केवल दोनों पक्षों की तरफ से पारंपरिक गश्त में व्यवधान का उल्लेख था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में हुई सैन्य वापसी के हिस्से के रूप में इन प्रथाओं को उनके पारंपरिक स्वरूप में बहाल किया गया है। सरकार ने संसद में ये विवरण साझा किए हैं। राजनाथ सिंह ने आगे लिखा– राहुल गांधी की तरफ से सेना प्रमुख के लिए कहे गए शब्द कभी भी सेना प्रमुख की तरफ से नहीं कहे गए थे। यह बहुत खेद की बात है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय हित के मामलों पर गैरजिम्मेदार राजनीति में लिप्त हैं। यदि कोई भारतीय क्षेत्र है जिसमें चीन घुसा है, तो वह 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किमी और 1963 में पाकिस्तान की तरफ से चीन को अवैध रूप से सौंपे गए 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र है। राहुल गांधी हमारे इतिहास के इस चरण के बारे में आत्मनिरीक्षण करने पर विचार कर सकते हैं। राहुल गांधी ने एक दिन पहले चीन के सीमा पर आक्रामक रुख को लेकर भी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने सदन में कहा कि श्चीन की सीमा पर आक्रामकता को लेकर सैन्य अधिकारियों के बयानों में अंतर है। चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है, इस बात से प्रधानमंत्री इनकार कर रहे हैं, लेकिन सेना ने पीएम के बयान से असहमति जताई है।

महाकुंभ हादसे में हुई मौतों को लेकर लोकसभा में सरकार से अखिलेश ने सवाल किए

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे में हुई मौतों को लेकर लोकसभा में सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने मामले में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने सरकार से मौतों, घायलों के इलाज और आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में सटीक आंकड़े पेश करने को कहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए अखिलेश ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने सिफारिश की कि आपदा प्रबंधन और खोया–पाया केंद्र को सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। अखिलेश ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि एक धार्मिक समागम में राजनीतिक प्रचार अशोभनीय, निंदनीय है। सरकार ने महाकुंभ का इतना प्रचार किया और मैंने कई टीवी इंटरव्यू और समाचार चौनलों पर ये बात सुनने में आई कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। अगर ये बात गलत है तो मैं इस्तीफा आपको देना चाहता हूं।श उन्होंने कहा, श्सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, लेकिन महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी बताए। मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया–पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ दुर्घटना में हुई मौतों, घायलों के उपचार, दवाओं, डॉक्टरों, भोजन, पानी, परिवहन की उपलब्धता के

आंकड़े संसद में पेश किए जाएं। सपा मुखिया ने सरकार के आंकड़ों को दबाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों और तथ्यों को छिपाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, श्महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और सच्चाई को छिपाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। हम डबल इंजन सरकार से पूछते हैं कि अगर कोई गलती नहीं थी, तो आंकड़ों को क्यों दबाया, छिपाया और मिटाया गया? अखिलेश ने कहा, श्लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर गए।श उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जहां उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन में राजनीतिक प्रचार करना, खासकर डबल इंजन वाली सरकार में, शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दावा किया गया था कि महाकुंभ डिजिटल तरीके से और आधुनिक तकनीक से आयोजित किया जाएगा। सीसीटीवी, ड्रोन और लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर डिजिटल कुंभ आयोजित करने का दावा करने वाले मृतकों का डिजिटल रिकॉर्ड भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि श्रद्धालुओं के शव मिल गए, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

पशिचम बंगाल राज्य का नाम बदलकर बांग्ला रखने की मांग

कोलकाता, (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग करते हुए कहा कि इसमें राज्य के इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, पार्टी सांसद रीताब्रत बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जुलाई 2018 में राज्य का नाम बदलने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र अभी तक इस पर सहमत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि श्पुनरू नामकरण हमारे राज्य के इतिहास, संस्कृति और पहचान के अनुरूप होगा और हमारे लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। 1947 के विभाजन ने बंगाल को विभाजित कर दिया। भारतीय हिस्से को पश्चिम बंगाल कहा गया और दूसरे हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि आज कोई पूर्वी पाकिस्तान नहीं है। हमारे राज्य का नाम बदलने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश का सम्मान करने की जरूरत है। किसी भी राज्य का नाम आखिरी बार 2011 में बदला गया था, जब उड़ीसा ओडिशा बन गया था।

संक्षिप्त समाचार

शशि थरूर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, मानहानि का मामला खारिज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया। यह मामला भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि याचिका से संबंधित है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने शशि थरूर को तलब करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत में मानहानि का कोई तत्व नहीं बताया गया है। राजीव चन्द्रशेखर ने अपनी याचिका में शशि थरूर को कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने, सार्वजनिक माफी मांगने और कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की। चंद्रशेखर ने दावा किया कि थरूर ने अप्रैल 2024 में उनके खिलाफ विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर झूठे और अपमानजनक बयान दिए, जिससे उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। चंद्रशेखर के अनुसार, थरूर ने एक टेलीविजन चौनल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कथित बयान दिया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि भाजपा नेता ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को पैसे की पेशकश की थी।

सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने मणिपुर में हिंसा पीड़ित विधवाओं

पुणे, (एजेंसी)। मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों की दुर्दशा से आहत होकर भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल ने विधवाओं को आजीविका कमाने में मदद करने और संघर्ष से प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। पुणे में पिछले माह सेना दिवस परेड के अवसर पर ले. कर्नल एल. मनोंगबा (सेवानिवृत्त) को इस पहल के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा 'वेट्रन अचीवर' पुरस्कार से सम्मानित किया था। मणिपुर में 35 विधवाओं की आजीविका के लिए उन्हें छोटे उद्यम शुरू करवाने और अपने पिताओं को खो चुके 60 बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए उनकी पहल को सराहना मिली। पूर्वोत्तर राज्य में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है और इस हिंसा के कारण सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे, संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। यह यात्रा संगम के पास महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के कुछ ही दिनों बाद हो रही है, जिसमें मौनी अमावस्या पर 'अमृत स्नान' के दौरान कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 लोग घायल हो गए थे। पीएम मोदी सुबह 10:05 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे 10:10 बजे डीपीएस हेलीपैड जाएंगे और उसके बाद 10:45 बजे एरियल घाट जाएंगे। सुबह 10:50 बजे वे एरियल घाट से नाव से महाकुंभ जाएंगे, जहां वे 11:00 से 11:30 बजे तक संगम घाट पर स्नान करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे महाकुंभ में पहुंचेंगे। वहां से वे अरैल घाट जाएंगे और गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम

संगम तक नाव की सवारी करेंगे। उनकी यात्रा में संतों से बातचीत, संगम में पवित्र डुबकी और महाकुंभ 2025 में भाग लेने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा शामिल होने की उम्मीद है। मेला अधिकारियों के अनुसार, मूल यात्रा कार्यक्रम, जिसमें राज्य मंडप और नेत्र कुंभ का दौरा शामिल था, को संशोधित किया गया है, और ये स्थान अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं। 5 फरवरी हिंदू परंपरा में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है, क्योंकि यह माघ अष्टमी और भीष्म अष्टमी का पालन करता है – दोनों धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं में गहराई से निहित हैं। माघ अष्टमी, हिंदू महीने माघ के आठवें दिन मनाई जाती है, इसे आध्यात्मिक गति विधियों के लिए एक शुभ समय माना जाता है। भक्त प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान, दान और ध्यान करते हैं।

देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है आप

पंजाब, (एजेंसी) पंजाब के अमृतसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर हुए हमले को लेकर विपक्षी दलों ने पंजाब और दिल्ली में सत्ता धारी आम आदमी पार्टी और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चौतरफा हमला बोल रखा है। इसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि देश के संविधान निर्माता का यह अपमान गणतंत्र दिवस के दिन थाने के पास में हुआ, इसलिए यह और भी गंभीर मामला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक खुद को दलितों का शुभचिंतक बताने की कोशिश करती रही है। यह राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीआर अंबेडकर के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम और सद्भावना दिखाने की कोशिश करती नजर आती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अभियान में भी यह दिखाया जाता है कि पार्टी के नेता संविधान निर्माता के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं। लेकिन, अमृतसर में हुई एक घटना ने पंजाब सरकार

को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। पंजाब में संविधान लागू होने की वर्षगांठ के दिन जो कुछ हो गया, उससे विपक्ष को राज्य की न सिर्फ कानून और व्यवस्था पर, बल्कि आप सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाने का कारण दे दिया है मामले को लेकर दलितों की पार्टी कहलाने वाली बीएसपी की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे सीधे तौर पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया है। उन्होंने एक्स पर ताबड़तोड़ कई पोस्ट लिखे हैं। पहले पोस्ट में वह कहती हैं, श्संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में स्थापित प्रतिमा खंडित करने व वहां संविधान की किताब के नजदीक आग लगाने का प्रयास शर्मनाक। सरकारी लापरवाही से हुई ऐसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम। आप की सरकार खुद को दलितों के लिए काम करने वाली सरकार कहती है, ऐसे में इस पर बसपा प्रमुख का हमला गंभीर सवाल उठा रहा है। बीजेपी ने भी पंजाब की भगवंत सरकार और आम आदमी पार्टी के लिए इस घटना के सिलसिले में जो कुछ कहा है, वह बहुत ही संवेदनशील है। पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अमृतसर में बीआर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा को आप की पंजाब सरकार की नाक के नीचे एक शख्स ने हथौड़े से क्षतिग्रस्त कर दिया।

महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर - पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होने वाली हैं। ऐसे में इस समय दिल्ली में राजनीनिक ड्रामा देखने को मिल रहा हैं। चारों तरफ जबरदस्त तरीके से मैदान में उतरी सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रटार कर रही हैं। ऐसे में भाजपा इस बार दिल्ली में एक प्रचंड जीत का दावा कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भारी जीत की ओर अग्रसर है। गोयल ने यहां भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर राजधानी के लोगों को स्वच्छ पेयजल, साफ हवा से वंचित करने और यमुना नदी के पुनर्जीवन जैसे अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सभी वर्ग के लोगों को नरेन्द्र मोदी और उनकी गारंटियों पर भरोसा है, पांच फरवरी भाजपा के लिए मील का पत्थर और दिल्ली के लोगों के लिए स्वर्णिम दिन साबित होगा।" केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो दिल्ली के विकास में बाधा डालने के बजाय काम करे और सेवा करे। गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जे पी नड्डा की सभाओं में लोगों की भारी भीड़ आने का उल्लेख करते हुए कहा, "महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत की तरह, भाजपा दिल्ली की सभी सीट पर भारी जनादेश के लिए तैयार है, इनमें वे सीट भी शामिल हैं जिन्हें पहले जीत पाना कठिन माना जाता था।" उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में पूर्वांचलियों, उत्तराखंडियों और अन्य प्रवासी समुदायों के साथ दिल्ली के मूल वासियों सहित सभी वर्ग के लोगों ने भाजपा को समर्थन देने का मन बना लिया है। संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की कथित विफलताओं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधूरे वादों पर एक वीडियो चलाया गया। गोयल ने आप सरकार पर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को अवरुद्ध करके और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को स्थायी आवास उपलब्ध न कराकर दिल्ली को विकास से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उसने दिल्ली में एक लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं लागू की हैं और इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लोगों और उनके हितों की परवाह करते हैं। गोयल ने बताया कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट ने लगभग पूरे मध्यम वर्ग को आयकर के बोझ से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग पूर्व भाजपा मुख्यमंत्रियों मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के युग को फिर से जीना चाहते हैं, जब शहर में विकास की लहर थी और वे अब भाजपा को एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। वर्ष 1993 में पहली बार दिल्ली की सत्ता में आयी भाजपा ने 25 साल से अधिक समय से राजधानी में विधानसभा चुनाव नहीं जीता है। दिल्ली में भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणी मुकाबला है। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और आठ फरवरी को मतगणना के साथ नतीजे घोषित होंगे।

वक्फ संशोधन विधेयक को लागू करने से सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती – ओवैसी

पंजाब, (एजेंसी)। पंजाब एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी है कि वक्फ संशोधन विधेयक को मौजूदा स्वरूप में लागू करने से सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। अपनी चिंताओं पर जोर देते हुए, ओवैसी ने सरकार को विधेयक पर आगे बढ़ने के प्रति आगाह किया। वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति ने 14–11 वोटिंग से मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में हिस्सा लेते हुए औवेसी ने कहा कि मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं– अगर आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं, जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा, तो इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। आप भारत को श्विकसित भारतश बनाना चाहते हैं, हम श्विकसित भारतश चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस देश को श्80 और 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हर मुसलमान को भारतीय होने पर गर्व है और वह अपनी जमीन छीनने नहीं देगा। ओवैसी ने कहा कि क्योंकि, एक गौरवान्वित भारतीय मुस्लिम के रूप में, मैं अपनी मस्जिद का एक इंच भी नहीं खोऊंगा।

संपादकीय

ट्रंप का टैरिफ युद्ध

राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी एजेंडे के साथ ही चीन, कनाडा व मैक्सिको पर भारी–भरकम टैरिफ थोपकर व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है। ट्रंप के फैसले से वैश्विक बाजारों में भूचाल है। इन तीनों देशों द्वारा इसका जबाब देने की घोषणा से विश्व व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। दरअसल, अमेरिका ने अपने शीर्ष व्यापारिक सहयोगी कनाडा व मैक्सिको पर 25 फीसदी और चीनी सामानों पर 10 प्रतिशत टैफिक थोपकर उन्हें आर्थिक प्रतिशोध हेतु बाध्य कर दिया है। कनाडा ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है तो मैक्सिको भी ऐसा मन बना रहा है। वहीं चीन पिछली टैरिफ लड़ाइयों से परेशान होकर रणनीतिक प्रतिशोध को तैयार है। वह इस मामले को विश्व व्यापार संगठन तक ले जाने की बात कर रहा है। हालांकि, भारत फिलहाल ट्रंप की संरक्षणवादी कार्रवाई से बचा नजर आता है। भारत ने टैरिफ कटौती की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रंप के उस टैरिफ दुरुपयोग के आक्षेप से बचने का प्रयास किया है, जिसको लेकर ट्रंप भारत को निशाने पर लेते हैं। दरअसल, भारत में शीर्ष तीस अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क मसलन कच्चे पेट्रोलियम से लेकर हार्ले–डेविडसन मोटर साइकिल तक पर मामूली टैरिफ हैं। निस्संदेह, यह रणनीतिक कदम न केवल तत्काल अमेरिकी प्रतिशोध ा को रोकता है बल्कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एकीकृत होने के लिये भारत की प्रतिबद्धता का भी संकेत देता है। जैसा कि केंद्रीय बजट 2025–26 में रेखांकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत अमेरिकी व्यापार घाटे में केवल 3.2 प्रतिशत का ही कारक है। इसकी वजह यह भी है कि भारत के तेजी से बढ़ते फार्मास्युटिकल और कीमती धातुओं के निर्यात फिलहाल कमजोर बने हुए हैं। यह अच्छी बात है कि ट्रंप ने पहले टैरिफ वार से भारत को राहत दी है, लेकिन वैश्विक व्यापार युद्ध से भारत में विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है। असर रुपये की सेहत पर भी पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा से द्विपक्षीय व्यापार खिड़की खुलने की संभावना है। वहीं ट्रंप की इस कार्रवाई का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि सामान पर टैरिफ बढ़ाए जाने से चीनी उत्पाद महंगे होंगे, तो भारतीय निर्यातक अमेरिका बाजार में नये अवसर तलाश सकते हैं। खासकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में। लेकिन इसके बावजूद भारत को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। इस टैरिफ जंग का एक पहलू यह भी कि अमेरिका में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को मुश्किल समय के लिये तैयार रहने के लिये कहा है। आशंका है कि इससे भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक में मांग कम हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कोई भी अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंध अंततरू भारत के प्रमुख उद्योगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, हमने उभरते वैश्विक आर्थिक युद्ध से बचने के लिये व्यावहारिक टैरिफ रणनीति को अपनाया है, लेकिन अभी भी बड़े वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका खत्म नहीं हुई है। हालिया केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में छूट देकर मध्य वर्ग को खुश तो किया है, लेकिन ट्रंप के व्यापार युद्ध की घोषणा से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में भारत को व्यापार संतुलन को बनाये रखने और ग्लोबल इकॉनमी पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के लिये तैयार रहना होगा। आशंका है कि कनाडा, मैक्सिको व चीन के बाद ट्रंप यूरोप को भी निशाने पर ले सकते हैं। एक अनिश्चितता पैदा हुई है कि यह टैरिफ युद्ध कितना और किस दिशा में बढ़ता है। आर्थिक विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं कि मोदी की अमेरिका यात्रा में ट्रंप भारत से व्यापार असंतुलन दूर करने को कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत अमेरिका से आधुनिक अस्त्र, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस तथा कृषि उत्पाद आयात बढ़ाकर टैरिफ युद्ध की छाया से बच सकता है। बाकी कुछ ट्रंप की प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करेगा। लेकिन साथ ही भारत को विश्व व्यापार संगठन के सभी देशों के लिए समान टैरिफ नियम का भी पालन करना होगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य भी सामने हैं।

दिल्ली के जनादेश की गूंज

जय प्रकाश

देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बुधवार, 5 फरवरी को दिल्ली के डेढ़ करोड़ से ज्यादा मतदाता, अपने–अपने वोट के जरिए दिल्ली की अगली सरकार को चुनेंगे। यह फैसला करेंगे कि वह दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से बनाने जा रहा है। दिल्ली के मतदाताओं ने किसे जनादेश दिया है,यह खुलासा तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही हो पाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि देश की राजधानी दिल्ली से निकले जनादेश की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। कहने को तो, यह भी कहा जा सकता है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य भी नहीं है और केवल 70 विधायकों वाली विध ाानसभा का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भला कैसे पड़ सकता है लेकिन यह तर्क अपने आप में पूरी तरह से गलत और बेमानी है। दिल्ली में वैसे तो मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का ही माना जा रहा है। लेकिन अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने कई विधानसभा सीटों पर चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। इंडिया गठबंधन के बिखरने की आशंका से डरे हुए कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव प्रचार अभियान के शुरुआती दौर में थोड़ी हिचक जरूर दिखाई। लेकिन बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जिस अंदाज में चुनावी रैलियां की, रोड शो किए,उसने दिल्ली की चुनावी लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है। दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी है, जो वर्ष 2013, 2015 और 2020 के बाद अब वर्ष 2025 में लगातार चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव आम आदमी पार्टी से ज्यादा उनके नेता अरविंद केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि दिल्ली की हार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर देगा और पार्टी के अंदर भी कई तरह के सवाल उठने लगेंगे। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा है जो देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल के अपने वनवास को खत्म करना चाहती है। इससे पहले भाजपा दिल्ली में 1993 में सत्ता में आई थी। वर्ष 1993 में चुनाव जीतकर भाजपा ने मदन लाल खुराना को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। जैन हवाला डायरी में नाम आने के कारण, खुराना को इस्तीफा देना पड़ा और साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा आलाकमान ने उन्हें हटाकर सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि वह भी दिल्ली में भाजपा को जीत नहीं दिला पाई और 1998 में कांग्रेस से हार कर पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ गई। दिल्ली के विध ाानसभा चुनाव में भाजपा को पहले कांग्रेस ने लगातार तीन बार हराया और उसके बाद आप भी लगातार 3 चुनाव हरा चुकी है। दिल्ली की चुनावी रेस में तीसरे नंबर की पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस इस बार सरकार बनाने से ज्यादा किंग मेकर के रूप में उभरना चाहती है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली कांग्रेस के लिए दिल्ली का यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है।

कारगर तंत्र बने महामारियों से निपटने को

राजेश

लोगों के जहन से कोविड–19 महामारी के दौरान हुई तबाही, मौतें और सामाजिक अफरातफरी का दृश्य और उससे पाई सीख धीरे–धीरे मिटती जा रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस किस्म की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की क्षमता रखने वाली महामारी न तो पहली स्वास्थ्य आपात स्थिति थी और न ही आखिरी। कोई भी असाधारण घटना, जो बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से सबके स्वास्थ्य के लिए जोखिम का कारण बन जाए, तो इसका मतलब है ऐसी गंभीर, अप्रत्याशित या असामान्य स्थिति बनना, जिससे निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। वर्ष 2007 से लेकर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर सात बार अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए हैं। जैसे कि, इन्फ्लुएंजा महामारी (2009), इबोला (2013–2015 और 2018–2020), पोलियो माइलाइटिस (2014 से अब तक), जीका (2016), कोविड–19 महामारी (2020) और एमपॉक्स (2022 और 2024)। उनकी आवृत्ति और प्रसार की नियमितता के आलोक में, तार्किक रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगली एक महामारी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सवाल है कि महामारी का कारण क्या है? वर्तमान सहस्राब्दी के दौरान, अधिकांश महामारियां वस्तुतः पशुओं से मनुष्यों में दाखिल हुए वायरस के कारण बनी हैं, जो मूलतः वन्यजीवों के अंदर होते हैं, जहां पर उनके अंदर लाखों–लाख वायरस पल रहे होते हैं। इनमें से अधिकांश वायरस चमगादड़ों के माध्यम से वन्यजीवों से आसपास के जानवरों और मानव बस्तियों में पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय स्तर के प्रकोप से लेकर बड़े पैमाने की महामारी बनती है या फिर महामारी बनने की संभावना बलवती हो जाती है। पर्यावरण का क्षरण, विशेष रूप से वनों की कटाई की वजह से, जंगली जीवों की निकटता घरेलू पशुओं एवं मानव बस्तियों से बढ़ जाती है, जिससे नए–नए वायरस के उभरने और फैलाव का खतरा पैदा हो जाता है। निरूसंदेह, नित बन रही इन आपात स्थितियों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उचित तैयारी के साथ, समुदायों के लिए बनने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक उपकरण–आधारित तंत्र विकसित करने और लागू करने के काम में समन्वय किया है। वर्ष 2005 का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 193 सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि है। यह राष्ट्रों से पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं की जानकारी साझा, स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, उनका पता लगाने और प्रतिक्रिया के लिए अपनी राष्ट्रीय कोर क्षमता का निर्माण करने का आह्वान करता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के स्व–मूल्यांकन के अनुसार, वैश्विक औसत 66 प्रतिशत के मुकाबले भारत का स्कोर 85 प्रतिशत रहा। लेकिन फिर भी, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को 42.8 स्कोर के साथ 195

मुल्कों में 66वें स्थान पर रखा गया है (वैश्विक औसत 28.4 है)। इस वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भविष्य की महामारी और महामारी के खतरों के परिप्रेक्ष्य में सभी देशों की तैयारी चिंताजनक रूप से नाकाफी है। जबकि संभावनाओं में कोविड–19 से कहीं अधिक विनाशकारी खतरे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक नियमों के अनुरूप बनने में भारत की क्षमता में तत्काल और व्यापक वृद्धि की आवश्यकता है। कोविड–19 महामारी से सीख लेते हुए, एक व्यापक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून की आवश्यकता है। भविष्य की महामारियों पर नीति आयोग के एक हालिया दस्तावेज ने आपातकालीन स्वास्थ्य प्रबंधन कानून लागू करने की सिफारिश की है ताकि किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, रोकथाम, नियंत्रण और प्रतिक्रिया बनाने के लिए त्वरित उपाय पहले से तैयार रहें। वैश्विक स्तर पर, पिछले दो वर्षों से विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देशों के बीच महामारी संधि पर बातचीत चल रही है, लेकिन आम सहमति न बन पाने की वजह से यह लटकी हुई है। विचार यह है कि कोविड–19 के दौरान की विफलताओं को स्वीकार करते हुए, अगली महामारी से पहले अथवा उसके दौरान सहयोग बढ़ाया जाए। भारत में उच्चतम तकनीकी स्तर पर वन हेल्थ मिशन की शुरुआत करना अच्छी बात है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के कार्यान्वयन में सभी क्षेत्रों को एक साथ लाने और आम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को उत्प्रेरित करने की क्षमता है। भारत ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। प्रमुख चुनौतियों में माइक्रो बायोलॉजिकल प्रयोगशालाओं को मजबूत करना शामिल है जो प्रारंभिक शिनाख्त और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वेब–आधारित एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से नजर रखने में प्रगति हुई है, जो हर हफ्ते औसतन 40–50 प्रकोपों का पता लगाता है। यह संक्रामक रोगों से संभावित राष्ट्रीय बोझ का सूचकांक है। महामारी से निपटने में विशेष रूप से भारत भर में प्रशिक्षित कार्यबल और फील्ड स्तर पर गुपचुप जानकारी जुटाने वाला एक मजबूत कार्यक्रम बनाने और विस्तार करने की फौरी जरूरत है। ताकि स्थानीय स्तर पर एक प्रभावी जांच एवं रोकथाम क्रियान्वयन तुरंत चलाया जा सके। राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम को समुदाय और अस्पतालों के डेटा तक सभी संबंधित क्षेत्रों की पहुंच निर्बाध और वास्तविक समय में उपलब्ध करवाने के लिए साझा एकीकृत डेटा पोर्टल सुविधा बनानी होगी ताकि उचित हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी असामान्य घटनाओं का जल्द पता लगाने के लिए मानव–पशु–वन्यजीव इंटरफेस पर आधारित एक कुशल एकीकृत निगरानी तंत्र महत्वपूर्ण है। गैर–स्वास्थ्य विशेषज्ञता संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए देश विशेष पर आधारित पूर्वानुमान और भविष्यवाणी मॉडल बनाने की आवश्यकता है। महामारी से निपटने में वैक्सीन सबसे किफायती स्वास्थ्य उपाय होता है। यह अविश्वसनीय था कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक, उद्योग और नियामक इस अवसर पर आगे आए और कम समय में प्रभावकारी कोविड–19 टीका विकसित और निर्मित किया। 100 करोड़ से अधिक लोगों को 220 करोड़ टीका लगाना वास्तव में सराहनीय है। भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए नए टीके, निदान और दवाओं के लिए, औषधीय एवं नवीन औषधि विकास पर केंद्रित एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका लक्ष्य फार्मास्युटिकल उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और नियामक प्राधिकरणों की नेटवर्किंग के माध्यम से समुदायों में उपयोग के लिए इनका विकास, उत्पादन और इन्हें उपयुक्त बनाना हो। कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि इस उद्देश्य के लिए संस्थान नहीं बनाए जाते। व्यवस्थित जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव रणनीति, जिसमें स्थानीय प्रासंगिक कारक शामिल हों, के माध्यम से चलाए अभियान में जनता सक्रिय रूप से सहयोग नहीं करती। भारत में, जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसमें से 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं और 82.5 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते है, 42.5 करोड़ लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, 897 टेलीविजन चौनल हैं, जिनमें से 350 समाचार चौनल हैं, इसके अलावा विभिन्न भाषाओं में लगभग 80,000 समाचार पत्र हैं, इनके जरिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तक व्यापक पहुंच है। इन संसाधनों का उपयोग देश की लगभग पूरी आबादी तक विश्वसनीय और व्यवहार्य स्वास्थ्य संदेश पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। नई बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और उनके प्रति व्यापक त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बनी राष्ट्रीय क्षमता भविष्य की महामारियों के प्रभाव को कम करने की कुंजी है। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और उचित निरंतर वित्त पोषण की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक अराजकता को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 ढांचे को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

जीवनशैली में सुधार से घातक रोग पर अंकुश संभव

योगेश

दुनियाभर में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ग्लोबोकॉन के मुताबिक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के चलते विश्वभर में 2040 तक कैंसर के मामले प्रतिवर्ष 2.84 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जो 2020 के मुकाबले 47 फीसद ज्यादा होंगे। वर्ष 2020 में दुनियाभर में अनुमानित तौर पर कैंसर के 1.93 करोड़ नए मामले आए थे और लगभग एक करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार कैंसर मरीजों की संख्या वैश्वीकरण और बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़े जोखिम कारकों में वृद्धि से बढ़ सकती है। लोगों को कैंसर के संभावित कारणों के प्रति जागरूक करने, प्राथमिक स्तर पर कैंसर की पहचान करने और शीघ्र निदान तथा रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनियाभर में प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बीएमजे ऑन्कोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की स्टडी के अनुसार पिछले 30 वर्षों में दुनियाभर में 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में कैंसर के नए मामलों में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान श्वासनली और प्रोस्टेट कैंसर के मामले सर्वाधिक रिपोर्ट किए गए, जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। 1990 के बाद से श्वासनली और प्रोस्टेट कैंसर सबसे तेजी से बढ़ा। 2019 की शुरुआत में स्तन कैंसर के मामले सर्वाधिक रिपोर्ट किए जा रहे थे, जिसका जोखिम बना हुआ है। स्तन, श्वासनली, फेफड़े, आंत और पेट कैंसर के कारण अभी भी सर्वाधिक मौतें रिपोर्ट की जा रही हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 में कैंसर के नए शुरुआती मामलों में 31 प्रतिशत और उससे जुड़ी मौतों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 के आंकड़ों के आधार पर रिसर्चर्स के मुताबिक– 2019 में 50 से कम उम्र के लोगों में कैंसर के नए मामलों की संख्या 1.82 मिलियन थी, जो 1990 के आंकड़े से 79 प्रतिशत अधिक थी। भारत में कैंसर के निरन्तर बढ़ रहे मामले स्वास्थ्य ढांचे के लिए गंभीर चुनौती हैं। प्री–मैच्योर मौत का सबसे बड़ा कारण माने जाने वाले कैंसर के मामलों का ग्राफ देश में लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में प्रतिवर्ष एक करोड़ से भी ज्यादा कैंसर के नए मामले सामने आते हैं और दुनिया के 15 फीसदी कैंसर मरीज भारत में हैं। कई मामलों में तो मरीज अपना इलाज तक नहीं करा पाते। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आगामी पांच वर्षों में कैंसर मामलों की संख्या 12 फीसदी बढ़ जाएगी। यहां कैंसर के 40 फीसदी से भी ज्यादा मरीज फेफड़े, स्तन, अन्नप्रणाली , मुंह, पेट, लीवर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से पीड़ित हैं, जिनमें फेफड़ों के कैंसर से 10.6 फीसद, स्तन कैंसर से 10.5, अन्नप्रणाली कैंसर से 5.8, मुंह के कैंसर से 5.7, पेट के कैंसर से 5.2, लीवर कैंसर से 4.6 और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से 4.3 फीसदी लोग पीड़ित हैं। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में कैंसर के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। आईसीएमआर तथा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉरमेटिक्स एंड रिसर्च (एनसीडीआईआर) के अनुसार भारत में कैंसर के कुल केसों का करीब 27 फीसदी तम्बाकू जनित होने की संभावना है। इसके अलावा स्तन कैंसर के 2.4 लाख जबकि फेफड़ों के कैंसर के 1.1 लाख तथा मुंह के कैंसर के 90 हजार मामले सामने आ सकते हैं । रिपोर्टों के अनुसार पुरुषों में कैंसर के 50 फीसदी मामले तम्बाकू के कारण होते हैं। अमेरिका के जाने–माने कैंसर विशेषज्ञ डा. जेम अब्राहम चेतावनी दे चुके हैं कि भारत को कैंसर जैसी क्रॉनिक बीमारियों की सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक वैश्वीकरण, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती आबादी और बदलती जीवनशैली के कारण ये मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए टीके, एआई, डेटा डिजिटल तकनीक का विस्तार, लिक्विड बायोप्सी से निदान, जीन एडिटिंग टेक्नॉलोजी का विकास एवं अगली पीढ़ी के इम्युनोथेरैपी तथा सीएआर टी सेल थैरेपी का इस्तेमाल कैंसर के उपचार को नया रूप देंगे । वहीं डिजिटल तकनीक, आईटी तथा टेली–हैल्थ से मरीजों एवं विशेषज्ञों के बीच खाई कम होगी। चुनौती होगी कि इन प्रौद्योगिकियों को लाखों लोगों के लिए कैसे सस्ता और सुलभ बनायें। डा. अब्राहम के मुताबिक, कैंसर मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को रोकने का एकमात्र विकल्प टीकाकरण है। ऐसे सभी टीकों पर परीक्षण जारी हैं। महामारी विज्ञान के अध्ययनों के अनुसार कैंसर के 70–90 फीसद मामले पर्यावरण से जुड़े हैं, जिनमें कैंसर का कारण बनने वाले पर्यावरणीय जोखिमों में जीवनशैली कारक सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सुधार करके कैंसर की सुनामी रोकना संभव है।

फोर्ब्स सूची में भारत के न होने के मायने

विनोद

प्रतिष्ठित संस्था फोर्ब्स ने साल 2025 के लिये 10 सर्वाधिक शक्तिशाली देशों की जो सूची जारी की है, उसमें भारत का नाम नहीं है। फोर्ब्स के इस रैंकिंग मॉडल को बीएवी ग्रुप ने तैयार किया है, जो कि डब्ल्यूपीपी यूनिट का हिस्सा है जिसका नेतृत्व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल के प्रो. डेविड रीबस्टीन करते हैं। वैसे इस सूची पर आलोचना भी हो रही है क्योंकि इसमें भारत जैसे विशाल व बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत को बाहर कर दिया गया, जबकि कुछ छोटे देशों को शामिल किया गया है। यह भी सही है कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी सेना विश्व की चौथी बड़ी है। यह रैंकिंग अपने आप में चौंकाने वाली बताई जा रही है और बहुत सम्भव है कि देश का सरकार समर्थक कुनबा तथा गोदी मीडिया इसे श्भारत के खिलाफ साजिशश तथा श्प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से उपजी पश्चिमी जगत की ईर्ष्याश करार दे सकता हैय लेकिन बेहतर होगा कि इस बात पर मंथन किया जाये कि ऐसा क्या हुआ कि अबकी देश का नाम इस सूची से हटा दिया गया है। फोर्ब्स की रैंकिंग पर सवाल उठाकर भारत अपनी जगहंसाई ही करायेगा क्योंकि पश्चिम जगत में होने वाले ऐसे निष्कर्ष, सर्वे और समीक्षाएं शत प्रतिशत चाहे न कहें तो भी ज्यादातर स्वतंत्र व निष्पक्ष होती हैं जिन्हें न तो किसी सरकार द्वारा प्रभावित किया जा सकता है और न ही कभी उनकी मंशा पर संदेह व्यक्त किया जाता है– फोर्ब्स के बारे में तो ऐसा कहा ही जा सकता है। इसलिये फोर्ब्स द्वारा दी गयी रैंकिंग पर ऊंगली उठाने की बजाये बेहतर है कि भारत सरकार उन कारणों की समीक्षा करे जिनके आधार पर देश को दसवां स्थान भी नहीं मिला। देश की स्थिति के लिये नेतृत्व ही जिम्मेदार होता है– साफ है कि मोदी सरकार की कमजोरी फोर्ब्स की सूची में फेरबदल करने के लिये उत्तरदायी है। फोर्ब्स की रैंकिंग के मुताबिक ताकतवर देशों का क्रम इस प्रकार है– अमेरिका (जीडीपी 30.34 ट्रिलियन डॉलर), चीन (19.53 ट्रिलि.), रूस (2.2 ट्रिलि.), यूनाइटेड किंग्डम (3.73 ट्रिलि.), जर्मनी (4.92 ट्रिलि.), दक्षिण कोरिया (1.95 ट्रिलि.), फ्रांस (3.28 ट्रिलि.), जापान (4.39 ट्रिलि.), सऊदी अरब (1.14 ट्रिलि.) और इजरायल (जीडीपी 550.91 बिलियन डॉलर)। यह जान लेना भी उचित होगा कि फोर्ब्स की यह रैंकिंग किन आधारों पर तय होती है। सर्वप्रमुख है नेतृत्व क्षमता। इसमें यह परखा जाता है कि देश का नेतृत्व कितना प्रभावशाली है। दूसरे, आर्थिक प्रभाव कितना है। इसका मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और व्यापक है। एक पैमाना यह भी है कि देश का राजनीतिक रसूख कैसा है। अर्थात वैश्विक राजनीति में उस देश की स्थिति कैसी है। अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को भी देखा जाता है। इसके अंतर्गत इस बात की पड़ताल होती है कि अन्य देशों के साथ उसकी कूटनीतिक साझेदारी की स्थिति कैसी है और सैन्य शक्ति जिसमें यह देखा जाता है कि देश की सेना कितनी मजबूत और आधुनिक है)। इन सभी मानकों के समग्र प्रभाव का असर रैंकिंग तय करता है।

कई देशों की अर्थव्यवस्था का आकार तो अधिक हो सकता है लेकिन नेतृत्व पर्याप्त सशक्त न हो तो उसका क्रमांक घट सकता है। ऐसे ही, अर्थव्यवस्था बड़ी हो, नेतृत्व भी प्रभावशाली हो लेकिन कूटनीतिक गठबन्धनों की दृष्टि से यदि वह देश प्रभाव नहीं छोड़ता तो उसका क्रमांक नीचे जा सकता है। वैसे देखें तो भारत अब भी बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी सेना का आकार पहले की ही तरह विशाल है। जिस तथ्य के कारण भारत को इस प्रतिष्ठित सूची से हटाया गया है सम्भवतरू वह है नेतृत्व का कमजोर होना। नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर कमजोर हुए हैं। पिछले साल हुआ लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में तथा उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था। लक्ष्य था अकेले भाजपा के दम पर 370 सीटें लाना और सत्ताधारी गठबन्धन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) की सम्मिलित ताकत को लोकसभा में 400 सीटों के पार ले जाना। ऐसा हो नहीं हो सका। भाजपा की सदस्य संख्या 240 पर सिमट गयी तथा उसे सरकार बनाने में काफी कठिनाई हुई। उनकी कमजोरी का असर संसद के भीतर सरकार के कामकाज पर दिख रहा है। 2014–19 तथा 2019–24 के दो कार्यकालों की तरह मोदी सरकार मनमर्जी निर्णय लेने की हैसियत नहीं रखती। उसे वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा। यह अलग बात है कि येन केन प्रकारेण सरकार उसमें अपनी मर्जी के संशोधन स्वीकृत कराने में सफल हो गयी। पिछली दो लोकसभाओं के मुकाबले लोकसभा में विपक्ष की स्थिति बेहतर हुई है और अनेक मुद्दों पर सत्ता पक्ष को प्रतिपक्ष को ध्यान से सुनना पड़ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र व हरियाणा के चुनावों में भाजपा को विजय मिली है, पर यह भी सच है कि वह जम्मू–कश्मीर व झारखंड में हारी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब नरेन्द्र मोदी का पहले जैसा असर नहीं दिखता। अमेरिका में नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी को पद की शपथ ली तब उस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया था। एक तरफ चीन को निमंत्रण दिया गया तथा दूसरी तरफ देश के प्रमुख कारोबारी मुकेश अंबानी को सपत्नीक न्यौता मिला था, ।

क्या होगा तेरा री दिल्ली?

राजेंद्र

हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस के पूरे मन से नहीं भी तो, आधे से ज्यादा मन से यह चुनाव लड़ने के पीछे, मतदाताओं के इस हिस्से का रिस्पांस भी हो। विडंबना यह है कि मतदाताओं के इसी हिस्से का रिस्पांस, कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के विपरीत आम आदमी पार्टी के साथ गठबंध ान में चुनाव न लड़कर, दोनों के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के चुनावी निहितार्थ को लेकर भाजपा को दुविधा में डालता है। सरल चुनावी गणित यह कहता है कि लोकसभा अब जबकि दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है और कम से कम सैद्धांतिक रूप से मतदाताओं को विवेकपूर्ण तरीके से अपना मन बनाने देने के लिए, श्प्रचार शांतिश् के घंटे शुरू हो चुके हैं, एक बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के 2013 के उसके पहले चुनाव को छोड़कर, सबसे मुश्किल विधानसभाई चुनाव साबित होने जा रहा है। ऐसा होने के दो स्वतरूस्पष्टङ्ख कारणों की तो अधिकांश टीकाकारों ने चर्चा की

है और उनका काफी कुछ विश्लेषण भी हुआ है। इनमें पहला कारण तो किसी हद तक नये जोश के साथ, कांग्रेस का पार्टी का लगभग सभी विध ाानसभाई सीटों पर उतरना और मुकाबले को किसी न किसी हद तक तिकोना बना देना ही है। बेशक, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने के दावे को दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत गंभीरता से लिया हो, ऐसा नजर तो नहीं आता है। इसमें शक नहीं कि चुनाव प्रचार के दौरान, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार से असंतुष्टङ्ख मतदाताओं के एक गौरतलब हिस्से में, दिल्ली में लंबे अर्से तक रही कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार के दौर के प्रति आकर्षण दिखाई दिया है। लेकिन, इससे इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है कि कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार से असंतुष्टङ्ख मतदाताओं के एक हिस्से को अपनी ओर खींचने में समर्थ है,

राजकीय आई0टी0आई0 में 07 फरवरी 2025 को रोजगार मेला का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर शासन की मंशा एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0 के निर्देश के क्रम में जिला सेवायोजन कार्यालय जौनपुर द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्दीकपुर कैम्पस जौनपुर में 07 फरवरी 2025 को प्रातः 10:00 बजे रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। जिसमें शिस्का एल0ई0डी0 इलेक्ट्रीकल, हीरो क्राप्ट मोटर प्रा0लि0, जे0पी0 वी0एम0जी0मार्ट, श्री गनेशा मैनेजमेंट सर्विस के द्वारा आफिस सुपरवाइजर, टी0पैकिंग एण्ड सेल्स, लोन ऑफिसर, आदि निजी क्षेत्र की कम्पनी के द्वारा विभिन्न पदों पर भती करेंगी, रोजगार मेलें में प्रतिभागी अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यताः– हाईस्कूल, इण्टर, आई0टी0 आई0 एवं स्नातक उत्तीर्ण एवं आयुसीमा 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थियों को भर्ती करेंगी। रोजगार मेलें में अभ्यर्थी अपने योग्यतानुसार प्रतिभाग करते हुए विभिन्न पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया की रोजगार मेला में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आई0डी0प्रुफ सहित एवं वेब पोर्टल https://rojgaarsangam.up.gov.in पर जॉबसीकर के रूप में पंजीकरण उपरांत आवेदन करते हुए, रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल एवं अन्य सहायक उपकरण का वितरण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश चन्द्र यादव के निर्देशानुसार विकास खण्ड–करंजाकला के परिसर में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग जौनपुर द्वारा आयोजित ट्राईसाइकिल एवं अन्य सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि करंजाकला जौनपुर सुनील यादव (मम्मन) के कर कमलों द्वारा ट्राईसाइकिल तथा अन्य सहायक उपकरण का वितरण जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा पेंशन, दुकान लोन, शादी अनुदान, यू0डी0आई0डी0 कार्ड के विषय में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा कुल 62 ट्राईसाइकिल, 07 स्मार्ट केने, 02 हियरिंग एड एवं 02 व्हीलचेयर का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी (पं0) डॉ0 रामकृष्ण यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी विनोद सहाय श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी (स0क0) आकाश यादव, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) मुकेश कुमार कन्नौजिया, ग्राम पंचायत अधिकारी नागेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अमित सोनकर, प्रमोद कुमार यादव, अवधेश यादव, संजीव मौर्य, मुकेश मौर्य, हरेन्द्र प्रताप यादव, नवनीत सिंह, विश्राम बिन्द तथा सफाई कर्मचारी संघ के ब्लक अध्यक्ष मंगला प्रसाद यादव, सुनील राव, जंगबहादुर यादव, अंजनी मौर्य तथा विकास खण्ड के एकाउन्टेन्ट जितेन्द्र श्रीवास्तव तथा घनश्याम भारती, वरिष्ठ सहायक तथा राहुल राजभर कम्प्यूटर आपरेटर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उपस्थित रहे।

पान की खेती पर उद्यान विभाग से मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी से किसानों का होगा लाभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिला उद्यान अधिकारी डॉ. सीमा सिंह राणा द्वारा अवगत कराया गया कि शासन की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की फसलों की खेती पर अनुदान दिया जाता है, इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत पान विकास योजना एवं गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। जनपद जौनपुर में ब्लाक महाराजगंज, सुजानगंज, मछलीशहर, बक्सा, करंजाकला में बहुत ही तकनीकी विधि से कृषको द्वारा पान की खेती की जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी डॉ0 सीमा सिंह राणा द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष उद्यान विभाग को 250 वर्ग मीटर का 7 पान बरेजा, 500 वर्ग मीटर का 7 पान बरेजा, 750 वर्ग मीटर का 5 पान बरेजा, 1000 वर्ग मीटर का 15 पान बरेजा एवं 1500 वर्ग मीटर का 2 पान बरेजा का लक्ष्य प्राप्त है। 250 वर्ग मीटर पान बरेजा पर रू0 12613, 500 वर्ग मीटर पान बरेजा पर रू0 25226, 750 वर्ग मीटर पान बरेजा पर रू0 37840, 1000 वर्ग मीटर पान बरेजा पर रू0 50453 एवं 1500 वर्ग मीटर पान बरेजा पर रू0 75680 का अनुदान देय है। इच्छुक कृषक भाई जो पान की खेती करते हो जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं। कृषकों का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा।

वसीरपुर घटना का आरोपी गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा गांव के अखड़ो घाट के पास बुधवार को पुलिस ने वसीरपुर गांव के चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से मिली सूचना पर ट्रेनी आईपीएस सीओ सिटी आयुष श्रीवास्तव थानाप्रभारी जयप्रकाश यादव मय फोर्स ऊक्त घाट के पास पहुंच गए।वहां पर वसीरपुर गांव में हुए गोलीकांड का आरोपी शंभु पुत्र बड़ेलाल निषाद मौजूद था।पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।ज्ञात हो ऊक्त गोलीकांड में वसीरपुर गांव के बीडीसी मनीष कुमार तथा सूरज कुमार को गोली लगी थी।इसके अलावा राजन को चाकू लगा था।तीन आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं।

अर्टिका कार एवं स्कार्पियो की टक्कर में कार सवार पांच लोग घायल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सिकरारा बक्शा थाना क्षेत्र के फतेहगंज बाजार के समीप प्रयागराज मार्ग पर मंगलवार की देर रात्री अर्टिका कार एवं स्कार्पियो की टक्कर में कार सवार कुल पांच लोग घायल हो गए। गम्भीर रूप से घायल तीन लोगों के बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। बुधवार को इस मामले में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल के

समीप रात करीब 1रू30 बजे जंघई बाजार निवासी मठोई गांव निवासी अर्टिका कार सवार 28 वर्षीय सुनील कुमार यादव, 30 वर्षीय मंजू यादव, 10 वर्षीय अदिति, 15 वर्षीय साक्षी यादव, 12 वर्षीय शिवम् यादव सिटी स्टेशन से उतरकर अपने घर जा रहें थे। कार सवार लोग जैसे ही फतेहगंज बाजार के समीप एक ढाबे के पास पहुँचे सामने से आ रही स्कार्पियो चालक अपनी कार को अचानक मोड़ दिया उसी समय पहुँची अर्टिका कार स्कार्पियो से जा टकराई। टक्कर होते ही कार में चीख पुकार मच गई। बाजार में ही मौजूद पुलिसकर्मियों एवं ग्रामीणों ने पहुँच कार सवार घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुँची 108 नम्बर एम्बुलेंस सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

बच्चेदानी का कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरे नम्बर का कैंसर है : डॉ शुभा सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।विश्व कैंसर दिवस पर जौनपुर ऑब्सटेट्रिक्स एवं गाइनीकोलॉजिकल सोसाइटी (जॉग्स) ने वृहद सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान चलाया। इसके अन्तर्गत सदस्य चिकित्सकों ने विभिन्न स्कूलों, नर्सिंग कॉलेजों एवं जौनपुर मेडिकल कालेज में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता शिविर लगाया। संस्था की अध्यक्ष डा० शुभा सिंह ने बताया कि बच्चेदानी का कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरे नम्बर का कैंसर है। अधिकांश रोगी कैंसर फैल जाने के बाद आते हैं जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। संस्था की उपाध्यक्ष डा० अन्जू कन्नौजिया ने बताया कि नियमित पैप स्मियर जाँच द्वारा कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में ही निदान कर उचित उपचार किया जा सकता है। सचिव डा० शैली निगम ने बताया कि कैंसर का टीका (एच०पी०वी० की वैक्सीन) लगवाने से इस कैंसर से बचा जा सकता है। यह टीका 9 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाओं को लगाया जा सकता है परन्तु जल्दी लगवाने पर (9–14 वर्ष) ज्यादा लाभदायक होता है। टीकाकरण का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए 13 सेन्टर्स पर घटी दरों पर टीकाकरण किया जा रहा है, जो इस माह के अन्त तक किया जायेगा। कैम्प का आयोजन करने वाले डाक्टर्स में डा० प्रियम्वदा सिंह, डा० शकुन्तला यादव, डा० शुभा सिंह, डा० मधु शारदा, डा० स्मिता, डा० अन्जू कन्नौजिया, डा० अम्बर खान, डा० शैली निगम, डा० संध्या सिंह, डा० सरिता पाण्डेय, डा० अन्शू कुमारी, डा० रेहाना परवीन, डा० चंचल मिश्रा, डा० बीना त्रिपाठी, डा० नशरा फातिमा और डा० शिल्पी सिंह रहे। इस कैम्प द्वारा करीब 1500 लोगों को जागरूक किया गया जिसमें बच्चे, उनके अभिभावक, शिक्षक एवं नर्सिंग स्टाफ शामिल रहे।

पलिया शाहबदी कृष्णा नगर वार्ड की महिलाओं ने लगाई विधायक अयोध्या से आशियाना बचाने की गुहार'

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। कृष्णा नगर वार्ड पलिया शाहबदी के निषाद बिरादरी समेत कई अन्य गरीब परिवारों को तहसीलदार सदर के द्वाराग्राम समाज की लाखों रुपए की जुर्माना नोटिस जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द इस जुर्माने को अदा करें अन्यथा स्वयं प्रस्तुत होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों ना आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए।इस विकट समस्या को लेकर आज पलिया शाहबदी कृष्णा नगर के पार्षद रमाशंकर निषाद की अगुवाई में गांव के सैकड़ो महिला पुरुष व पीड़ित मनोज कुमार, श्रीमती, प्रदीप, रामदेयी विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता से मिलने आए।विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता अस्वस्थ होने के बावजूद पीड़ितों को सम्मानपूर्वक बैठाकर उनकी समस्या को पूरे मनोयोग से सुना।ग्राम वासियों का कहना है कि उन्हें डर है कि उनके आवासों को भी हटाया जाएगा।वो सब इतने गरीब हैं कि उनके पास तो अन्य जगहों पर 1 इंच भूमि भी नहीं है कि अपना घर बनाकर रह सके।विधायक श्री गुप्ता ने पूरी बात सुनने के उपरांत कार्यवाही करते हुए तहसीलदार सदर को पूरे प्रकरण से अवगत कराने के लिए कहा।

साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब असहाय लाचार महिला का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभी इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की वसूली न की जाए।उन्होंने सभी को अवगत कराते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीबों के हित के लिए सदैव तत्पर है और चाहे वह सरकारी हो अथवा सामाजिक किसी भी स्तर पर उनका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

इस प्रकरण को मैं पूरी तरह वार्ता कर जल्द ही सुलझाने का प्रयास करूंगा।विदित हो की नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता इधर कई दिनों से पैर में फ्रैक्चर की वजह से अस्वस्थ हैं और चिकित्सकों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है। परंतु मिल्कीपुर उपचुनाव में वह जीतोड़ मेहनत करते हुए डटे हुए थे उन्होंने विभिन्न बाजारों में बैठक और सम्मेलन आयोजित कराते हुए लोगों से जनसंपर्क कर प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रिकॉर्ड वोटो से जीतने की अपील भी करते रहे।

विधायक की ये कर्तव्य निष्ठा और पार्टी के प्रति समर्पण की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है।क्षेत्र की जनता समेत भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।इस अवसर पर अमल गुप्ता, मोनू सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बी.आर.सी. पर दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण एवं उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं पर दिया गया प्रशिक्षण।

जौनपुर । दिनांक 04/ 01/ 2025 को ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) सिरकोनी पर समेकितध्‍ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण उनके उत्थान तथा उपस्थितिध्ठहराव हेतु प्रारम्भ हुये नोडल शिक्षकों के प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस में आज दिनांक 05–02–2025 को बच्चों के अन्दर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत क्रमशरू लोकोमोटर(चलन दिव्यांगता), आरटिज्म (स्वलीनता अर्थात अपने ही धुन में मस्त रहने वाली दिव्यांगता), मानसिक मन्दता (मानसिक दिव्यांगता) तथा मिर्गी (म्बसपचेम) के विभिन्न प्रकारों , उनके उत्पन्न होने के कारण तथा उनसे बचाव व आवश्यक प्राथमिक उपचार आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए नोडल शिक्षकों को टीचर प्रशिक्षण के द्वितीय मॉड्यूल का संदर्भ दाता श्री विक्रांत सिंह (प्रधानाध्यापक प्रा.वि.सिरकोनी जौनपुर)द्वारा बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण करते हुए सटीक ढंग से समझाया गया तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन तथा बुनियादी साक्षरता मे सपोर्ट हेतु अपने विचारों को प्रशिक्षण के दौरान रखा गया। इसके साथ ही संदर्भदाता श्री विक्रांत सिंह के द्वारा होम बेस्ड एजुकेशन , समर्थ मोबाइल एप तथा दिव्यांग जनों की शिक्षा मे सूचना संप्रेषण तकनीकी पर विशेष रूप से फोकस करते हुए आज का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आज के इस प्रशिक्षण में स्पेशल एजूकेटर श्री प्रमोद कुमार दूबे, स्पेशल एजूकेटर श्री राममनोहर भारती तथा स्पेशल एजूकेटर श्री शक्ति सिंह तथा स्पेशल एजूकेटर श्रीमती रेनू सिंह द्वारा अपना अनवरत सहयोग प्रदान किया।यह प्रशिक्षण दिनांक 04ध01ध2025 से प्रारंभ होकर अनवरत 5 दिन तक संचालित होते हुए दिनांक 08/01/2025 को समाप्त होगा।

सिद्धार्थनगर के उसका बाजार में पांच एकड़ में बनेगा कंपोजिट स्कूल

बस्ती, संवाददाता। लोक निर्माण विभाग का बस्ती भवन खंड सिद्धार्थनगर के उसका बाजार स्थित माध्यमिक विद्यालय के पांच एकड़ जमीन में कंपोजिट स्कूल का निर्माण करवाएगा। इसके लिए इंजीनियरों की टीम डीपीआर तैयार करने में लग गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस हाईटेक स्कूल का निर्माण शुरू हो जाएगा। शासन ने प्रदेश के 44 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बस्ती मंडल के सिद्धार्थनगर का भी चयन किया गया है। इस स्कूल पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जहां कक्षा एक से 12वीं तक स्मार्ट क्लास, लैंग्वेज लेन व स्किल सेंटर संचालित होगा। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय उसका बाजार का चयन किया गया है। जहां मानक के अनुसार साढ़े पांच एकड़ जमीन उपलब्ध है। पीडब्ल्यूडी भवन खंड के सहायक अभियंता राकेश सिंह और अवर अभियंता आरपी चौधरी के अनुसार, इस स्कूल में प्री–प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई एक ही छत के नीचे मिलेगी। स्मार्ट क्लास, स्किल हब सेंटर, कंप्यूटर, लैंग्वेज लैब, बहुउद्देश्यीय हॉल व प्रधानाचार्य और स्टाफ के लिए आवास बनाए जाएंगे। एक से कक्षा आठ तक कंपोजिट विज्ञान–गणित प्रयोगशाला, नौ से कक्षा 12 तक रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के लिए मॉड्यूलर लैब, आरओ वाटर प्लांट, मिड–डे–मील किचन, डायनिंग हॉल और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभाग इन मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराएगा। बताया कि यहां तीन मंजिला दिव्यांग सुलभ भवन भी बनाया जाएगा। प्रदेश के रामपुर, हाथरस, भदोही, बदायूं व बहराइच में कारपोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व (सीएसआर) के माध्यम से ओएनजीसी निर्माण करवाएगा। बाकी जिलों में राज्य सरकार निर्माण कराएगी।

अधिवक्ताओं के पास आने बालों को विश्वास होता है कि वकील उसे न्याय दिलाएंगे : रजनी तिवारी

हरदोई(अम्बरीष सक्सेना)

अधिवक्ता सदैव दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहते हैं। लोगों को विश्वास है तभी तो लोग अधिवक्ता के पास आते है न्याय के लिए और वकील उनके हक को, उनकी लड़ाई, को वकील हर प्रकार की समस्याओं से लडने के लिए अधिवक्ता सदैव जनहितैषी की भूमिका में होता है और लोगों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करता है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अधिवक्ता झगड़ता है वह न्याय दिलाने के लिए तहसीलदार से भी झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा की अधिवक्ता अगर झगड़ते है तो लोगों के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और इसके साथ ही अधिवक्ता तहसीलदार की तारीफ भी करते है जो मैं देख रही हूं। उन्होंने खुशी प्रकट करते हुए नव निर्वाचित कमेटी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने तहसील में लाइब्रेरी बनवाने का भी आश्वासन दिया साथ ही नव निर्वाचित महामंत्री अमित गुप्ता ने अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान व वाहन पार्किंग की व्यवस्था किए जाने की मांग रखी। जिसे उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने भी अधिवक्ताओं को जीत की शुभकामनाएं देते हुए विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि उपजिलाधिकारी दीक्षा जोशी, न्यायिक उपजिलाधिकारी गरिमा सिंह, तहसीलदार अजय कुमार गुप्ता, सहित त्रिपुरेश मिश्र आदि उपस्थित मंचासीन , सहयोगियों व शुभ चिंतकों को स्मृति चिन्ह व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। नवगठित कार्यकारिणी को उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने शपथ ग्रहण कराई।

नव निर्वाचित अध्यक्ष गोविंदराम दीक्षित ने समस्त अधिवक्ताओं का स्वागत व अभिनंदन किया।साथी अधिवक्ताओं मे अमितेश् मिश्रा सौरभ दुबे सौरभ त्रिवेदी आरती मिश्रा विशाल मिश्रा आकाश विपिन सार्थक वैभव दीक्षित शिखर त्रिपाठी विन्धुल मिश्रा सत्येंद्र यादव, सत्यम सक्सेना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र आदि का विशेष सहयोग रहा।

दो कारों के टक्कर में एक महिला घायल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । जलालपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर चौराहे पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दो कारों में टक्कर हो गई जिसे एक महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई ।प्राप्त जानकारी के अनुसार जलालपुर चौराहे पर एक बाइक सवार अचानक मडियाहू रोड से थाना गद्दी रोड पर निकला तभी वाराणसी की तरफ से आ रही कार बाइक सवार के बचने के चक्कर में शिवकुमार यादव निवासी आजमगढ़ ने अपनी कार का पावर ब्रेक मारा जिससे पीछे से आ रही कार ने आगे वाली कार में टक्कर मार दिया जिससे कार में बैठी आशा अंकुशपुरी निवासी पुणे महाराष्ट्र गंभीर रूप से घायल हो गई और कार में सवार उनके बेटे संदीप और श्याम प्रजापति लव कुश यादव बाल बाल बच गये। यह सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ मे स्नान करने के लिये जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को 108 एंबुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी ले गये जहां पर उसका उनका इलाज चल रहा है।

मूल्यांकन मे परीक्षको के प्रारिश्रमिक भुगतान में लाखों की अनियमिता का मामला वित्त अधिकारी पर गिरी गाज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को शासन से अटैच कर दिया गया और फैजाबाद विश्वविद्यालय के वित्तअधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वाराणसी मंडल आयुक्त मामले की जांच करेंगे ।मामला विश्वविद्यालय मूल्यांकन में परीक्षको के पारिश्रमिक भुगतान में भारी अनियमितता के कारण कार्रवाई हुई। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में परीक्षको के प्रारिश्रमिक भुगतान में भारी वित्तीय अनियमित उजागर होने के बाद प्रदेश शासन ने निर्णायक कदम उठाया। विश्वविद्यालय प्रशासन में वित्तीय हेराफेरी के इस प्रकरण में वित्त अधिकारी संजय कुमार राय को शासन से अटैच कर दिया। उनके जगह राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ला को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी सौंप गई है। वित्त अधिकारी संजय कुमार राय को उत्तर प्रदेश कोषागार लखनऊ से सब्धद किया गया है । वाराणसी मंडलायुक्त को इस संबंध में जांच करेंगे। मामला मई जून जुलाई 2023 का है ।जब तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने वित्तीय अनियमितता को गम्भीरता से लेते हुए एक कर्मचारी को बर्खास्त और एक अन्य को निलंबित कर दिया था । हालांकि जांच में उच्च पदस्थ अधिकारी बचाव में लग रहे ।घोटाले की जांच को तत्कालीन कुलपति ने तीन सदस्यीय समित का गठन किया था । जिसमें समिति के प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को स्पष्ट किया। इसमें सेवानिवृत्ति सदस्य न्यायाधीश और च चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट में इससे कुछ अलग रहा। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि परीक्षको की प्रारिश्रमिक के नाम पर चहेते व बाहरी व्यक्तियों के खाते में लाखों रुपए स्थानांतरित किए गए । मामला उजागर होने लगा तो वित्त अधिकारी संजय कुमार राय ने कुछ धनराशि वापस मंगवा कर नगद जमा करने का प्रयास किया। लेकिन घोटाले की जद में कई लोग आए । मामला 13 से 14 लाख का रहा। इस मामले को लेकर तरह–तरह की चर्चाएं हैं।

पछतावा नहीं..डबल मर्डर का खौफ जता रौब जमा रहा बाल अपचारी

गोरखपुर, संवाददाता। जो भी आंख दिखाएगा, उसका यही हश्र करूंगा। मुझे बार–बार चिढ़ाते थे, किसी की क्या औकात, मेरे सामने सिर उठाने की... सहजनवां के भक्सा गांव के दो किशोरों की हत्या का मुख्य आरोपी बाल सुधार गृह में रखे गए अन्य अपचारियों से कुछ इस तरह दहशत भरी कहानी सुना रहा है। वारदात को अंजाम देने का उसे कोई पछतावा नहीं है। बल्कि वह डबल मर्डर को अपनी उपलब्धि बताकर दहशत फैला रहा है। बाल सुधार गृह में उसकी गतिविधियों को देखते हुए विशेष सुरक्षा में रखा गया है। सुरक्षा कर्मी उसकी निगरानी में लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में डबल मर्डर का आरोपी कुकर्म के मामले में बाल सुधार गृह भिजवाया गया था। वह करीब आठ माह तक यहां रहा था। रविवार को दोबारा बाल सुधार गृह में आने पर कुछ पुराने साथी भी मिल गए हैं। वह साथियों से यह कहते फिर रहा है कि आने वाले दिनों में दहशत बनाकर राज करेंगे। पुराने बाल अपचारी की तरह वहां पर वह व्यवहार कर रहा है। पहले दिन से उसके आगे पीछे पुराने अपचारी सेवा सत्कार में लग गए हैं। जेल अधीक्षक किशोर केएम मिश्रा का कहना है कि उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। उसकी हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 700 से अधिक नंबरों की सीडीआर निकलवाई थी। इसके बाद वह पकड़ में आया। वहीं दूसरे नाबालिग आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 नंबरों की सीडीआर निकलवाई थी। वर्तमान में ये नंबर स्वीच ऑफ हैं। पुलिस के अनुसार, कई जगहों पर लोकेशन मिलने पर पहुंचे, इससे पहले ही वहां से आरोपी भाग गया। सहजनवां से पकड़ा गया मुख्य आरोपी वर्ष 2023 में बाल सुधार गृह में कुकर्म के मामले में रखा गया था। तभी आरोपी के बगल के गांव का किशोर भी हत्या के प्रयास के मामले में वहां भेजा गया। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई थी। पुलिस के अनुसार, 23 जनवरी की शाम भक्सा गांव के अभिषेक और प्रिंस की हत्या दोनों दोस्तों ने मिलकर की थी। मुख्य आरोपी को अभिषेक चिढ़ाता था। इसके बाद मिलकर हत्या कर दी। भेद खुलने के डर से अभिषेक के साथ आए ममेरे भाई प्रिंस को भी जान से मार दिया था। अभिषेक का परिवार उसकी हत्या के बाद बहुत डरा हुआ है।

मिल्कीपुर उपचुनाव : रामजी की शरण में भाजपा... रामटोली बनाकर बांटा जा रहा प्रसाद, पूरी ताकत झोंक दी

लखनऊ, संवाददाता। अयोध्या के मिल्कीपुर का रण रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। यहां मुख्य रूप से भाजपा व सपा की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों दलों ने जीत का ताज पहनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय सपा सांसद अवधेश प्रसाद का रोते हुए वीडियो राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय बना हुआ है तो भाजपा भी जीत सुनिश्चित करने के लिए अंत में राम जी की शरण में चली गई है। संघ, विहिप व अन्य आनुषांगिक संगठनों की ओर से मिल्कीपुर के मतदाताओं को रामलला का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। रामटोली बनाकर बूथ विजय अभियान के क्रम में विद्यार्थी परिषद की ओर से मंगलवार से रामलला का प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं संघ के कार्यकर्ता पहले से ही प्रसाद वितरण का अभियान चला रहे हैं। संघ का लक्ष्य अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने बताया कि रोजाना बैठकें कर शत–प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। बूथ विजय अभियान के तहत राम टोली तैयार की गई हैं। यह टोली मिल्कीपुर के बूथ क्षेत्रों में रामलला का प्रसाद घर–घर तक पहुंचाएगी। प्रसाद का वितरण मंगलवार को किया जाएगा। इसके लिए 70 बूथ चिन्हित किए गए हैं। 70 बूथ संयोजक भी बनाए गए हैं। ये बूथ संयोजक अपने–अपने बूथ क्षेत्रों में रामलला का प्रसाद वितरित करेंगे। मतदाताओं से शत–प्रतिशत मतदान करने की अपील करेंगे। मिल्कीपुर सीट भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। भाजपा ने जीत के लिए दिन–रात एक कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं चुनाव की कमान संभाल रखी है। चुनाव अभियान के दौरान सात बार मुख्यमंत्री मिल्कीपुर की जनता के बीच पहुंचे। सरकार के आधा दर्जन मंत्री, संगठन की टीम लगातार चुनाव क्षेत्र में कैंप किए हुए है। दोनों डिप्टी सीएम का भी दौरा हो चुका है। पर्दे के पीछे से संघ व उसके आनुषांगिक संगठन भी लगे हुए हैं। भाजपा को यहां जीत मिलती है तो अयोध्या की हार के घाव पर मरहम की तरह होगी यदि हार मिली तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। जबकि सपा के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठापरक है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र यहां किस्मत आजमा रहे हैं। दलित–पासी वोटों का गठजोड़ सपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जीत से अवधेश प्रसाद का राजनीतिक कद भी बढ़ जाएगा।

पोलिंग पार्टियां रवाना, पांच फरवरी को है मतदान, वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी

लखनऊ, संवाददाता। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर सोमवार को शाम पांच बजे थम गया। मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। पांच फरवरी को मतदान और आठ फरवरी को मतगणना होगी। 414 मतदेय स्थलों पर मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 210 मतदेय स्थलों पर वेब कास्टिंग के साथ 25 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बताया कि उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। इसके लिए 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्बर, नौ उड़न दस्ता टीम, नौ स्थैतिक निगरानी टीम, छह वीडियो निगरानी टीम टीम, दो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, चार जोनल मजिस्ट्रेट व 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। डीएम ने बताया कि 97.26 प्रतिशत मतदान पर्चियां वितरित की जा चुकी हैं। बाकी बची मतदाता पर्ची का वितरण बीएलओ की ओर से शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन मतदाताओं को किसी कारणवश मतदान पर्ची नहीं मिलती है तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अन्य विकल्प दिए गए हैं। इसमें आधार

कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पैन कार्ड समेत कुछ अन्य विकल्प शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल ीजजचेरूध्ध्अवजमते.मबप.हवअ.पद से भी मतदाता सूचना पर्ची को डाउनलोड किया जा सकता है। एसएसपी राजकरन नय्यर ने बताया कि पांच फरवरी को होने वाले मतदान के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मानक के अनुसार सुरक्षा कार्मिक मंगलवार को पोलिंग पार्टी रवानगी के साथ मतदेय स्थल पर पहुंच जाएंगे। बाकी अपने–अपने क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं। उपचुनाव को भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिल्कीपुर क्षेत्र के मतदाता व निवासी चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत होने पर उसकी जानकारी तत्काल दें। भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। शत प्रतिशत मतदान करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख बढ़ी

लखनऊ, संवाददाता। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर मंगलवार को एमपी–एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश दिनेश नागर की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 फरवरी तय की। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के लिए अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने संसद सत्र का हवाला देते हुए आरोपी सांसद को जमानत देने की अपील की। गौरतलब है कि 17 जनवरी को एक महिला नेता ने सांसद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने 30 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही जमानत याचिका पर अंतिम फैसला सुनाएगी।

रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की हालत गंभीर

लखनऊ, संवाददाता। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास (87) को ब्रेन स्ट्रोक के बाद लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। रविवार की देर रात मुख्य पुजारी की तबियत बिगड़ने पर उन्हें दर्शननगर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। जहां से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। उन्हें प्राइवेट अस्पताल हर्षण संस्थान ले जाया गया, हालत में सुधार न होने पर पीजीआई में भर्ती कराया गया। पीजीआई की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत बहुत गंभीर है। मौजूदा समय में उन्हें न्यूरोलॉजी वार्ड एचडीयू में भर्ती किया गया हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। वह मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं। उनकी हालत गंभीर है। वे फिलहाल स्थिर हैं। आचार्य सत्येंद्र दास एक मार्च 1992 से रामलला की सेवा में है। वे बाबरी विध्वंस से लेकर मंदिर निर्माण तक की यात्रा के साक्षी भी हैं। टेंट से लेकर भव्य महल में रामलला की सेवा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। उनके शिष्य व राम मंदिर के सहायक पुजारी प्रदीप दास ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में पूजा–अर्चना करने वाले आचार्य सत्येंद्र दास की तबियत बिगड़ने से मंदिर प्रशासन और उनके भक्तों में चिंता का माहौल है। सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

प्रदेश के मदरसों में अब नहीं चलेंगी कामिल–फाजिल की कक्षाएं, हजारों बच्चों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिह्न

लखनऊ, संवाददाता। मदरसों में अब कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) की कक्षाएं संचालित नही होंगी। मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में संचालित हो रहीं कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में करीब 37000 छात्र–छात्राओं के भविष्य पर असमंजस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल की डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असांविधानिक घोषित कर दिया था। शासन के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने कामिल और फाजिल पाठयक्रम में नए प्रवेश पर रोक लगा दी थी। कामिल और फाजिल की डिग्री की भाषा विश्वविद्यालय से संबद्धता का मामला शासन स्तर पर तय होने के बाद पहले से पढ़ रहे कामिल और फाजिल के विद्यार्थियों के भविष्य पर फैसला लिया जाना था। शासन स्तर पर निर्णय होने की स्थिति में बोर्ड ने अब मदरसों में चल रही कक्षाएं बंद करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने सभी जिलों को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेज कर कहा है कि कोर्ट से डिग्री असांविधानिक होने के बाद मदरसों में कामिल और फाजिल का पठन–पाठन या अध्यापन नहीं किया जा सकता है। न ही कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि कामिल और फाजिल के विद्यार्थियों का मामला हाईकोर्ट में है। कोर्ट से निर्णय के बाद तय हो पाएगा कि आगे क्या किया जा सकता है। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त और अनुदानित 16460 मदरसों में कामिल प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में करीब 28000 छात्र–छात्राएं और फाजिल के प्रथम व द्वितीय वर्ष में करीब 9000 छात्र–छात्राएं शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मदरसा एजुकेशनल एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मदरसों में पढ़ रहे कामिल और फाजिल के करीब 37000 विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर बना असमंजस अब भी खत्म नहीं हुआ है।

मुख्य स्टार प्रचारक होने के बाद भी दूर रहीं मायावती, अकेले आकाश आनंद ही दिखे मैदान में

लखनऊ, संवाददाता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य स्टार प्रचारक होने के बावजूद बसपा अध्यक्ष मायावती ने कोई भी रैली अथवा जनसभा को संबोधित नहीं किया। दिल्ली में दलित वोट बैंक के अपने मजबूत आधार के बावजूद उन्होंने प्रचार की पूरी कमान अपने भतीजे एवं पार्टी के नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद के कंधों पर डाल दी। मायावती के इस फैसले के अब सियासी निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। बता दें कि बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन के बाद दिल्ली चली गई थीं, हालांकि उन्होंने किसी भी जनसभा में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली में बसपा की सभी बड़ी जनसभाओं का नेतृत्व आकाश आनंद ने ही किया। जानकारों की मानें तो मायावती ने पार्टी में आकाश आनंद का कद बढ़ाने और उन्हें उत्तराधिकार को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी आकाश आनंद को ही नेतृत्व सौंपा गया था, जिन्होंने गठबंधन से लेकर तमाम अहम फैसले लिए थे। हरियाणा के बाद दिल्ली की राजनीति में भी आकाश के पैर जमाने पर पूरा फोकस रखा गया है। बसपा सुप्रीमो का दिल्ली से खास लगाव है। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने वहीं उच्च शिक्षा तक ग्रहण की। उनका सियासी सफर भी दिल्ली से शुरू हुआ था। वह अधिकतर दिल्ली और लखनऊ में ही रहती हैं। दिल्ली में बसपा का खासा वोट बैंक भी रहा है, जिस पर बीते कुछ वर्षों में आम आदमी पार्टी अपना दखल बढ़ाती रही है।

भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को करें ट्रेस : डीएम

लखनऊ, संवाददाता। शहर को बाल भिक्षावृत्त से मुक्त कराने के उद्देश्य से गठित की गई टीमों की हकीकत डीएम ने सोमवार को देखी। डीएम विशाख जी ने पॉलीटेक्निक और जीपीओ चौराहे का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शहर के पांच मुख्य चौराहों पॉलीटेक्निक, आईजीपी, अवध, जीपीओ व चारबाग पर नगर निगम, प्रोबेशन कार्यालय की संयुक्त टीम लगाकर सिग्नल्स पर भिक्षावृत्ति करने वालों की निगरानी कर रही है। भिक्षावृत्ति करने वालों की काउंसिलिंग कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। डीएम ने पॉलीटेक्निक व जीपीओ चौराहे पर टीम के साथ संवाद कर कहा, स्थानीय थाने से समन्वय कर भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को ट्रेस करने में सहयोग लिया जाए। साथ ही उनके परिवारों की काउंसलिंग कर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए।

संक्षिप्त समाचार

अर्जुनगंज फ्लाईओवर का निर्माण शुरू, साल भर में होगा पूरा

लखनऊ, संवाददाता। सेतु निगम ने केसरीखेड़ा फ्लाईओवर के बाद सुल्तानपुर रोड पर एक और अर्जुनगंज में फ्लाईओवर का निर्माण शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि यह निर्माण एक वर्ष में पूरा हो जाएगा। फ्लाईओवर बनने से जनता ही नहीं वीआईपी काफिले का आवागमन भी सुगम हो जाएगा। यहां आवागमन प्रभावित किए बिना फ्लाईओवर के पिलर का प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया है। एजेंसी अब पिलर की ढलाई शुरू करने जा रही है। सेतु निगम अफसरों ने बताया कि निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। आधारशिला 15 जनवरी को रखी गई थी। यह फ्लाईओवर लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर मरी माता मंदिर से लेकर अर्जुनगंज की तरफ 30 मीटर लंबा होगा। दोनों ओर एप्रोच मार्ग 300 मीटर लंबा होगा। यानी 150 मीटर अर्जुनगंज और 150 मीटर मरी माता मंदिर से पहले का मार्ग होगा। इससे आवागमन में सहूलियत मिलेगी। लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर वीआईपी काफिले का आवागमन काफी बढ़ गया है। इससे काफिला वाया अहमामऊ होकर शहीद पथ होते हुए एयरपोर्ट से लेकर कानपुर की ओर सुगमता से आवागमन करता है। मगर, अर्जुनगंज से अहमामऊ के बीच दोनों तरफ 20 से ज्यादा नव विकसित कॉलोनियों का यातायात बढ़ गया है। इससे अर्जुनगंज के पास सड़क संकरी पड़ने लगी और जाम में वीआईपी काफिले फंसने लगे।

प्रदेश में 40 हजार गुर्दा रोगी डायलिसिस पर

लखनऊ। यूपी में करीब 40 हजार गुर्दा रोगी डायलिसिस पर हैं। डोनर के इंतजार में करीब 40 फीसदी मरीज प्रत्यारोपण नहीं करा पा रहे हैं। गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा कुछ ही संस्थानों में है। सरकारी संस्थानों में हर साल करीब 350–400 गुर्दा प्रत्यारोपण हो रहे हैं। तमिलनाडु में कैडवरिक प्रत्यारोपण अधिक हो रहे हैं। ये बातें सोमवार को बलरामपुर अस्पताल के 156वें स्थापना दिवस समारोह में केजीएमयू नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विश्वजीत सिंह ने कहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा रहे। उन्होंने कहा, हर साल पांच हजार नए गुर्दा मरीज डायलिसिस पर जा रहे हैं। ऐसे में मरीज को जल्द गुर्दा प्रत्यारोपण करा लेना चाहिए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा, मरीजों को गुणवत्तापरक इलाज डॉक्टर मुहैया कराए। सरकारी अस्पतालों के प्रति मरीजों का भरोसा बढ़ा है। इलाज की गुणवत्ता के साथ शोधा को भी बढ़ाएं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह, परिवार कल्याण महानिदेशक डॉ. सुषमा सिंह, महानिदेशक प्रशिक्षण डॉ. पवन कुमार अरुण, बलरामपुर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी, निदेशक डॉ. सुशील प्रकाश आदि ने विचार रखे। केजीएमयू रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने कहा, टीबी को खत्म करने के लिए सभी की सहभागिता की जरूरी है। खांसी, बुखार व बेवजह वजन गिरने पर सजग हो जाएं। इसके लिए 100 दिनों का अभियान चलाया जाएगा। बलरामपुर अस्पताल में नवनिर्मित माड्लर आई ओटी व वार्ड का उद्घाटन मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को करना था। इसे स्थगित कर दिया गया है। अफसरों का कहना है उद्घाटन की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

सनतकदा महोत्सव के खानपान स्टॉल में लगी आग से मचा हड़कंप

लखनऊ, संवाददाता। कैसरबाग स्थित सलेमपुर हाउस में चल रहे सनतकदा महोत्सव में सोमवार को भीषण आग लग गई। लपटों की चपेट में आकर पांच फ्रीजर के कंप्रेसर फट गए। तेज धमाका होने से भगदड़ मच गई। इस दौरान एक कर्मचारी घायल हो गया। अग्निशमन विभाग की पांच गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के ाबाद आग पर काबू पाया हादसे में 15 स्टॉल जलकर राख हो गए। आयोजक ने फायर विभाग से कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं ली थी। सफेद बारादरी के पास 29 जनवरी से सनतकदा महोत्सव चल रहा है। इसकी आयोजक माधवी कुकरेजा हैं। सोमवार दोपहर दो बजे महोत्सव में लगे चाट के स्टॉल में छौंक लगाया जा रहा था। इस दौरान कढ़ाई में आग की तेज लपटें ऊपर उठी और शामियाने ने आग पकड़ ली। हवा तेज के चलते आग ने मिनट भर में भयावह रूप ले लिया। देखते ही देखते ही लपटों ने अन्य 14 स्टॉलों को चपेट में ले लिया। ऊंची–ऊंची लपटें देखकर भगदड़ मच गई। महोत्सव में काम कर रहा एक कर्मचारी गिरकर चोटिल हो गया। कुछ देर में ही सीएफओ मंगेश कुमार और एफएसओ हजरतगंज रामकुमार रावत तीन गाड़ियों के साथ पहुंचे। जूट से बने स्टॉल के कारण लपटें विकराल हो गईं। इसके बाद दो और गाड़ियां बुलाई गईं। लपटों की चपेट में आकर एक के बाद एक करके पांच कंप्रेसर फटने से लोग दहल गए। घटना के समय परिसर में करीब 150 लोग मौजूद थे। सभी को बाहर निकाला गया। धमाकों की गूंज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। इससे वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। इस दौरान एक अग्निशमन यंत्र भी फट गया। 15 स्टॉल व उसमें रखे सामान पूरी तरह जल गए। एफएसओ राम कुमार के मुताबिक स्टॉल में घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडर का इस्तेमाल हो रहा था। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले सिलिंडर को स्टॉल से बाहर फेंका। आग खुले में लगी थी, जिसके कारण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। सीएफओ ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। सलेमपुर हाउस व सफेद बारादरी में चल रहे सनतकदा महोत्सव में कई लापरवाही बरती गईं। एफएसओ ने बताया कि महोत्सव की आयोजक ने अग्निशमन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। आवेदन तक नहीं किया था। इतने बड़े महोत्सव में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण भी नहीं थे। इससे बड़ी संख्या में लोगों की जान खतरे में थी। विभाग की ओर से आयोजक को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके का आसमान धुंए से काला हो गया था।

मैनपुरी के महिला अस्पताल में इस्तेमाल हो रही फटी बेडशीट व पुराने कंबल

लखनऊ। महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं को परखने के लिए राज्य महिला आयोग टीम के सदस्य प्रदेश के सभी जिलों में निरीक्षण करते हैं। इन्हीं निरीक्षण के दौरान टीम को मैनपुरी जिले के करहल स्थिति खराब मिली। यहां मरीजों को फटी बेडशीट तो पुराने कंबल देने का मामला सामने आया है। सोमवार को गोमतीनगर में हुई राज्य महिला आयोग की बैठक में के बाद अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी महिला अस्पतालों में सुधार के निर्देश दिए हैं। आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने अध्यक्ष को बताया कि उन्होंने मैनपुरी के करहल में बीते माह महिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। यहां मरीजों को पुरानी बेडशीट व फटे कंबल दिए गए थे। परिसर में गंदगी थी। बैठक व कार्यशाला में महिला आयोग की प्रदेश भर की सदस्य शामिल हुईं। यहां शासन की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने बैठक में बीते माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला जनसुनवाई, वन स्टाप सेंटर, महिला अस्पताल आदि ।

हेट्रोजेक्शन टेक्नॉलोजी के टॉपकॉन और लिफ्टवर्टर खूब भा रहे

लखनऊ, संवाददाता। शहर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगे सोलर एक्सपो में नई तकनीक के उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। साधारण रूफ टॉप पैनल की जगह लोग हेट्रोजेक्शन टेक्नॉलोजी के टॉपकॉन पैनल को पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। टरी व अन्य उत्पाद हैं, लेकिन नई तकनीक के उत्पादों के बारे में सोलर इंडस्ट्री से जुड़े व घरों अथवा ठेके पर सोलर पैनल लगवाने वाले लोग ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सोलर पावर डेवलपमेंट एसोसिएशन के संरक्षक तारिक नकवी बताते हैं कि सोलर इंडस्ट्री से जुड़े प्रदेश भर के लोग यहां विजिट कर रहे हैं और पसंदीदा मॉडल को बुक कर रहे हैं। ऐसे एक्सपो इंडस्ट्री को बड़ा बाजार देते हैं। हरियाणा बेस्ड एक कंपनी ने हेक्ट्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी आधारित टॉप कॉन पैनल बनाया है, जो हाई डिमांड में है। कंपनी के मालिक आनंद ने बताया कि पैनल की सतह पर छोटे–छोटे सेलों के पास कई रास्ते बने होते हैं, जिन्हें बस बार कहते हैं। कहा कि पूरे एक्सपो में उनके पास ही एचजेटी टॉप कॉन है, जिसे उन्होंने प्लेन शार्क नाम दिया है। सामान्य पैनल में 10 बस बार होते हैं तो इसमें 16 हैं। इससे वह ज्यादा तीव्रता से सौर ऊर्जा को अवशोषित कर पावर जनरेट करता है। यह अपेक्षाकृत 10 फीसदी महंगा है, लेकिन जल्दी और ज्यादा रिजल्ट देने वाला है। एक्सपो में एक नामी कंपनी के लिफ्टवर्टर के बारे में भी सबसे ज्यादा पूछताछ हो रही है। कंपनी के रीजनल हेड आशुतोष तिवारी बताते हैं कि भरोसेमंद सर्विस के साथ हमारी तकनीक लोगों को पसंद आ रही है। लिफ्टवर्टर हाई डिमांड में हैं, जिनकी कीमत 3 लाख से शुरू है। इससे बिजली चली जाने पर अपार्टमेंट या भवनों में लिफ्ट नहीं रुकेगी।

एकेटीयू फाइलों में रुकेगा झोल, शुरू होगा ई–ऑफिस

लखनऊ, संवाददाता। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में पिछले कुछ सालों से लगातार फाइलों में हेरफेर की जांच चल रही है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने यहां ई–ऑफिस को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। इसका ट्रायल हो चुका है। इसे इसी सप्ताह से प्रभावी बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कुलपति कार्यालय से की जाएगी। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि ई–ऑफिस व्यवस्था प्रभावी होने से कामकाज में पारदर्शिता आएगी।

राजस्व निरीक्षक को हुआ ब्रेन हैमरेज, कर्मचारियों ने नगर निगम को घेरा

लखनऊ, संवाददाता। नगर निगम के राजस्व निरीक्षक शिवेंद्र मिश्रा को ब्रेन हैमरेज हो गया है। उन्हें रविवार देर शाम मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब अन्य निरीक्षकों और कर्मचारी नेताओं ने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि गृहकर वसूली बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारी बीमार पड़ रहे हैं। शिवेंद्र मिश्रा को इसी दबाव के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ। हालांकि, निगम प्रशासन ने आरोपों को नकारा है। नगर निगम जलकल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शशि मिश्र का कहना है कि नगर निगम अवकाश में कर्मचारी को छुट्टी नहीं देता, उस दिन कैंप लगा देता है। रात तक वसूली की मीटिंग होती है, जिससे कर्मचारियों का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह और संगठन मंत्री मोहम्मद रेहान ने कहा कि गृहकर वसूली के दबाव के कारण कर निरीक्षक रमेश गिरि दो महीने से बीमार हैं। उनका मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। नगर निगम जोन तीन के जोनल अफसर अमरजीत सिंह और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि जिन दो कर्मचारियों के बीमार होने की बात आई है उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है। वह अवकाश पर थे। वसूली को लेकर दबाव बनाए जाने का आरोप गलत है। इधर, सोमवार को नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह व अन्य अधिकारी राजस्व निरीक्षक को देखने अस्पताल गए। राजस्व निरीक्षक के बीमार पड़ने की आड़ लेकर सोमवार को 30 से अधिक राजस्व निरीक्षक गृहकर वसूली के लिए न तो फील्ड में गए और न ही कार्यालय में बैठे। वे अस्पताल में ही निगम प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, जिससे गृहकर वसूली भी प्रभावित हुई। कर्मचारी की सेहत पहले खराब है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002

RNI NO - UPHIN/2022/86937

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।